गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 273
दि. 04.02.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का जिला कलेक्टरों से आह्वान- आगामी मानसून से पहले ही जल संचय के कार्यों का अग्रिम आयोजन कर बरसाती पानी के अधिकाधिक संचय और संग्रह के जरिए जल संचय के क्षेत्र में गुजरात का नेतृत्व बनाए रखें

▸▸ मुख्यमंत्री ने राज्य में 'जल संचय जनभागीदारी 2.0' अभियान के कामकाज की सर्वग्राही समीक्षा के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह आह्वान किया

▸▸ इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल और विभाग के सचिव श्री कांताराव और केंद्र सरकार के अन्य अधिकारी दिल्ली से तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास सहित वरिष्ठ सचिव गांधीनगर से शामिल हुए

जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य में 'जल संचय जनभागीदारी 2.0' अभियान के कामकाज की सर्वग्राही समीक्षा के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक में दिल्ली से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री वी.एल. कांताराव और केंद्र सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ गांधीनगर से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास और वरिष्ठ सचिव शामिल हुए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्य के बनासकांठा, कच्छ और राजकोट जिले के कलेक्टरों के प्रेजेंटेशन सहित विभिन्न जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 'जल संचय जनभागीदारी 2.0' अभियान की प्रगति और आगामी आयोजन की विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और उनका समाधान देने का मार्गदर्शन मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कैसे प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए 'कैच द रेन' अभियान और जल संचय की राष्ट्रव्यापी मुहिम का अधिक से अधिक लाभ गुजरात को मिले।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिला कलेक्टरों को सीख देते हुए कहा कि वे भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने जिलों में बरसाती पानी के संग्रहण और संचयन के कार्य करें। ये सभी ऐसे जनहित के कार्य हैं, जिनसे कर्तव्य निभाने के कार्य संतोष के साथ-साथ आत्मसंतोष भी मिलता है।

मुख्यमंत्री ने ऐसा वातावरण बनाने की हिमायत की जिसमें राज्य के जिलों के बीच जल संचय-जनभागीदारी अभियान के कार्यों को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और जिन जिलों में जल संचय का काम कम हुआ हो, उन्हें भी अधिक कार्य करने का बल मिले।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक को जल संचय-जल संग्रह के कार्यों के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान आवंटित किया है, इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करें कि इसका भी उपयोग जिलों में जल संचय के कार्यों के लिए हो।

मुख्यमंत्री ने बैठक में जल संचय के व्यापक कार्यों को तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया ताकि केंद्र सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी योजना के अंतर्गत राज्य को आवंटित 553 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता का संपूर्ण उपयोग मार्च-2026 से पहले हो जाए।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि जल संचय-जल संग्रह क्षेत्र में गुजरात ने जो कार्य किया है, वह देश में

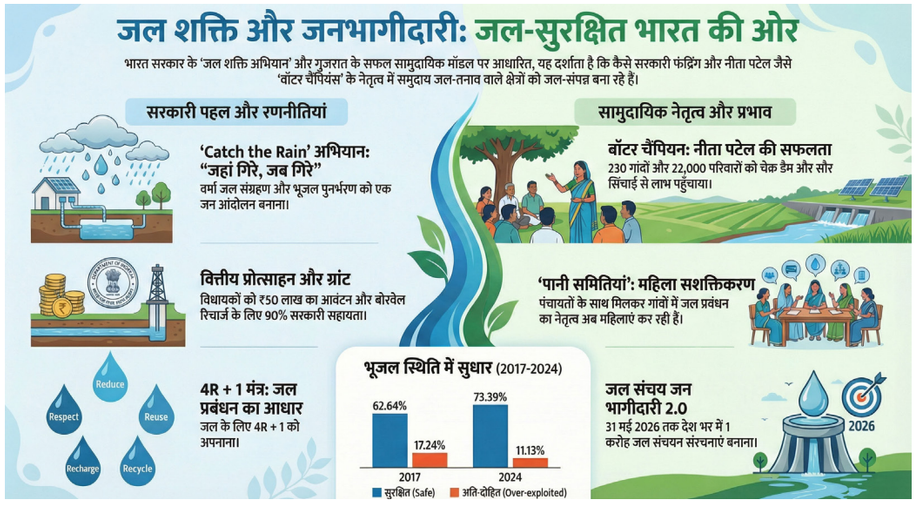

मॉडल बन गया है।

उन्होंने कहा कि पुराने बोर रिचार्ज करने की 70 फीसदी राशि केंद्र सरकार द्वारा देने के निर्णय से बड़ा लाभ हुआ है। उन्होंने जल संचय के कार्यों में अधिक संख्या में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जोड़ने के लिए एक सूची बनाकर उन्हें प्रेरित करने पर जोर दिया।

श्री पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में लागू होने वाली विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत मिलने वाले फंड का 40 फीसदी जल संचय-जल संग्रह के कार्यों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, ऐसा उदार प्रावधान किया गया है।

उन्होंने इस योजना के अंतर्गत समय पर और योजनाबद्ध तरीके से धन खर्च करने का मार्गदर्शन देते हुए कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से वाटर स्ट्रक्चर बनाकर जल संचय-जल संग्रह क्षमता में निरंतर वृद्धि से प्रधानमंत्री के जल सुरक्षा-जल आत्मनिर्भरता का संकल्प पूरा हो सकेगा।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने चालू वर्ष में जल संचय जन भागीदारी 2.0 अभियान के तहत आगामी 31 मई, 2026 तक देश भर में एक करोड़ से अधिक जल संग्राहक स्ट्रक्चर बनाने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए गुजरात में जल संचय के अधिकतम कार्य अगले मानसून से पहले पूर्ण करने का सुझाव दिया।

बैठक में इसकी भी समीक्षा की गई कि जल संचय जन भागीदारी 01 अभियान के तहत गुजरात में कुल 1,33,522 जल संचय के कार्य पूरे किए गए हैं तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज ट्यूबवेल, तालाब गहरा करने, खेत तालाब और फिल्टर वेल जैसे जल संचय के कार्य होने से भूगर्भ जल रिचार्ज में बड़ा फायदा हुआ है।

मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने इस बैठक में जल संचय-जन भागीदारी अभियान 2.0 की उज्ज्वल सफलता के लिए सभी जिला कलेक्टरों को मिशन मोड में कार्यरत होने का सुझाव दिया।

समीक्षा बैठक में जलापूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल, प्रधान सचिव श्री धनंजय द्विवेदी, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव डॉ. अजय कुमार तथा जल संसाधन सचिव श्री पी.सी. व्यास भी मौजूद रहे।

"मेरा टिकट, मेरी शान - विकसित भारत के लिए मेरा योगदान"

जन-जागरूकता अभियान में भावनगर की माननीय विधायक एवं महापौर की गरिमामयी सहभागिता

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा रेल यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा डिजिटल रेलवे सेवाओं के अधिकाधिक उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री तरूण जैन के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से संचालित "मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" अभियान के अंतर्गत दिनांक 03 फरवरी, 2026 (मंगलवार) को भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर एक प्रभावी जन-जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में भावनगर की माननीय विधायक श्रीमती सेजलबेन पंड्या, महापौर श्री भरतभाई बारड, उपमहापौर श्रीमती मोनाबेन पारेख, एम्बुलेंस 108 के हेड श्री कपिल सोलंकी, सौराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के श्री अशोक कोटाडिया सहित अन्य स्थानीय गणमान्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने के महत्व से अवगत कराया और यह

संदेश दिया कि टिकट लेकर यात्रा करना केवल एक कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिकता का प्रतीक है। इस पहल के माध्यम से यात्रियों में जिम्मेदार एवं अनुशासित यात्रा की भावना को और अधिक सुदृढ़ किया गया।

इस अवसर पर वाणिज्य विभाग द्वारा यात्रियों को रेलवन ऐप (RailOne App) की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। ऐप के प्रमुख लाभों जैसे — आसान टिकट बुकिंग, ट्रेनों की रीयल-टाइम जानकारी तथा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न रेलवे सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया तथा यात्रियों को डिजिटल सेवाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह अभियान यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने, डिजिटल रेलवे सेवाओं को अपनाने तथा एक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल रेलवे प्रणाली के निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करता है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी से अपील की है कि सभी यात्री उचित टिकट लेकर यात्रा करें और यह संदेश जन-जन तक पहुँचाएं।

इस अभियान से यात्रियों में रेलवे नियमों, नागरिक कर्तव्यों, ईमानदार यात्रा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में नई जांच की दस्तक, 'वीआईपी' कनेक्शन पर उठेगा से पर्दा

जीएनएस)। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगभग ढाई साल बाद एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। न्याय की आस लगाए बैठे परिजनों और आम लोगों के लिए यह खबर बेहद अहम मानी जा रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में औपचारिक रूप से केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड सरकार की सिफारिश पर दिल्ली स्थित सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच (ब्रांच-2) ने कथित 'वीआईपी' एंगल को केंद्र में रखते हुए जांच का जिम्मा संभाल लिया है। सितंबर 2022 में ऋषिकेश के पास वनतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रहीं अंकिता भंडारी की हत्या ने जिस तरह पूरे देश को झकझोर दिया था, वह आज भी लोगों की यादों में ताजा है। अब सीबीआई की एंट्री से एक बार फिर उम्मीद जगी है कि इस जघन्य अपराध से जुड़े हर सच को सामने लाया जाएगा।

अंकिता भंडारी की हत्या के बाद शुरुआती जांच में ही यह मामला बेहद संवेदनशील बन गया था। आरोप लगे थे कि अंकिता

पर एक प्रभावशाली व्यक्ति को "विशेष सेवा" देने का दबाव बनाया जा रहा था और इसी के चलते उसकी जान गई। हालांकि, उस समय स्थानीय पुलिस और एसआईटी की जांच में मुख्य आरोपियों के तौर पर रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, उसके सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकिता गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। बावजूद इसके, जनमानस में यह सवाल लगातार उठता रहा कि जिस कथित 'वीआईपी' का जिक्र शुरुआती दिनों से हो रहा था, उसकी पहचान अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई। इसी सवाल ने समय-समय पर इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला खड़ा किया।

करीब दो साल बाद यह मामला दोबारा तब गरमाया जब भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर से जुड़ा एक ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वायरल सामग्री में उर्मिला सनावर ने फेसबुक लाइव के दौरान अंकिता हत्याकांड में एक प्रभावशाली 'वीआईपी' की संलिप्तता का खुलकर जिक्र किया। इस दावे ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी। देखते ही देखते उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। जगह-जगह प्रदर्शन हुए, मोमबत्तियां जलाई गईं और सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। जन आक्रोश और लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 जनवरी को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ अब सीबीआई ने औपचारिक तौर पर केस दर्ज कर लिया है। माना जा रहा है कि सीबीआई की जांच का मुख्य फोकस उसी 'वीआईपी' एंगल पर होगा, जिसे लेकर अब तक सबसे ज्यादा सवाल उठते रहे हैं। जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश करेगी कि क्या अंकिता की हत्या के पीछे कोई और प्रभावशाली चेहरा था, जिसे पहले की जांच में बचा लिया गया या जिसका नाम जानबूझकर सामने नहीं आने दिया गया।

इस मामले ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में महिला सुरक्षा, सत्ता के दुरुपयोग और न्याय प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे।

नक्सलवाद के अंत की ओर देश, 2026 तक पूर्ण सफाया का सरकार का दावा

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक बेहद आश्वस्त करने वाली तस्वीर पेश की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को सदन को बताया कि दशकों से देश के कई हिस्सों में हिंसा, भय और अविकास का कारण बना वामपंथी उग्रवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सरकार का दावा है कि मौजूदा रणनीति, सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई और विकास आधारित दृष्टिकोण के चलते मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। आंकड़ों के साथ रखी गई यह जानकारी बताती है कि बीते डेढ़ दशक में नक्सली हिंसा में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है और उग्रवादियों का नेटवर्क लगातार कमजोर पड़ा है।

लोकसभा में लिखित और मौखिक उत्तर के दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि वर्ष 2010 के मुकाबले 2025 तक नक्सली हिंसा की घटनाओं में लगभग 88 प्रतिशत की कमी आई है। यह गिरावट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। जिन इलाकों में कभी सुरक्षाबलों पर हमले, सड़कें उड़ाना और आम नागरिकों की हत्या आम बात थी, वहां अब धीरे-धीरे शांति लौट रही है। सरकार का कहना है कि यह सफलता किसी एक कदम का नतीजा नहीं, बल्कि लंबे समय से अपनाई जा रही बहुस्तरीय रणनीति का परिणाम है।

पिछले सात वर्षों के आंकड़े इस बदलाव की गवाही देते हैं। इस दौरान 7,400 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे उनके संगठनात्मक ढांचे को गहरा झटका लगा है। इसके अलावा 5,880 नक्सलियों

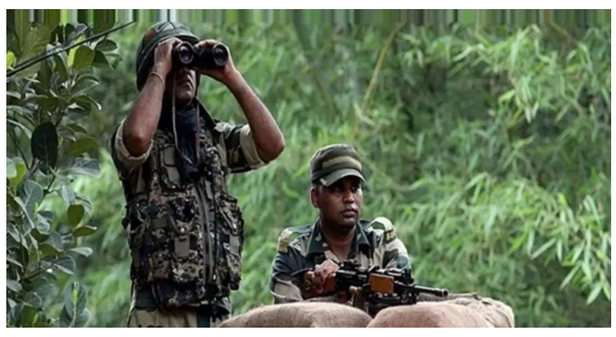

ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का रास्ता चुना है। आत्मसमर्पण करने वालों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं, जो वर्षों तक जंगलों में रहकर हिंसा का हिस्सा बने रहे, लेकिन अब उन्होंने समाज के साथ दोबारा जुड़ने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति ने उग्रवादियों को बंदूक छोड़ने के लिए प्रेरित किया है।

सिर्फ गिरफ्तारियां और आत्मसमर्पण ही नहीं, बल्कि सुरक्षा बलों की सटीक कार्रवाई ने भी नक्सल संगठनों को कमजोर किया है। पिछले एक साल में ही 364 नक्सलियों को मुठभेड़ों में मार गिराया गया, जबकि 1,022 को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 2,337 नक्सलियों का आत्मसमर्पण दर्ज किया गया, जिसे सरकार ने अब तक का रिकॉर्ड बताया है। इन आंकड़ों से साफ है कि नक्सली संगठनों के लिए न तो जंगल सुरक्षित रह गए हैं और न ही स्थानीय समर्थन पहले जैसा बचा है।

सरकार ने यह भी बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों का दायरा तेजी से सिमटा है। वर्ष 2018 में जहां देश के 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित माने जाते थे, वहीं दिसंबर 2025 तक यह संख्या घटकर केवल आठ जिलों तक रह गई है। इनमें से भी महज तीन जिले ऐसे हैं, जिन्हें 'अत्यधिक प्रभावित' की श्रेणी में रखा गया है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि नक्सलवाद अब राष्ट्रीय स्तर की समस्या नहीं रह गया, बल्कि कुछ सीमित इलाकों तक सिमट चुका है।

इसी तरह, नक्सली हिंसा की घटनाएं दर्ज करने वाले पुलिस थानों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। वर्ष 2010 में देशभर में 465 पुलिस थाने ऐसे थे, जहां नक्सली घटनाएं दर्ज होती थीं। अब यह संख्या घटकर केवल 119 रह गई है। सरकार के अनुसार, यह गिरावट सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता का परिणाम है। कई ऐसे इलाके, जो पहले पुलिस और प्रशासन की पहुंच से बाहर माने जाते थे, अब वहां नियमित गश्त, विकास कार्य और सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं।

नित्यानंद राय ने सदन में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की नीति सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है। 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के साथ-साथ विकास को हथियार बनाकर नक्सलवाद की जड़ों पर वार किया गया है। सड़कों का निर्माण, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार तथा स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने जैसे कदमों ने उग्रवादियों के प्रभाव को कमजोर किया है। जिन क्षेत्रों में कभी नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाते थे, वहां अब धीरे-धीरे सरकारी संस्थाएं मजबूत हो रही हैं।

सरकार का मानना है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मार्च 2026 की समयसीमा इस बात का संकेत है कि आने वाले महीनों में सुरक्षा बल बचे हुए गढ़ों में अंतिम और निर्णायक अभियान चलाने की तैयारी में हैं। हालांकि, यह भी स्वीकार किया गया कि यह लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि विश्वास और विकास से जीती जाएगी। स्थानीय आबादी का भरोसा जीतना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना इस रणनीति का अहम हिस्सा है।

लोकसभा में रखे गए इन आंकड़ों और दावों के बाद यह साफ है कि केंद्र सरकार नक्सलवाद को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि, यह भी उतना ही सच है कि बचे हुए इलाकों में चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से हिंसा में गिरावट, गिरफ्तारियों और आत्मसमर्पण के आंकड़े सामने आए हैं, उससे यह उम्मीद मजबूत हुई है कि देश जल्द ही उस दौर को पीछे छोड़ देगा, जब नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार अपने तय समय के भीतर इस लंबे संघर्ष को पूरी तरह समाप्त कर पाती है।

संपादकीय

रक्षा बजट से रणनीतिक शक्ति तक: गुणवत्ता, आत्मनिर्भरता और भारत की सुरक्षा चुनौती

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक रणनीतिक दृष्टि का हिस्सा है, जिसमें आर्थिक स्थिरता, तकनीकी क्षमता, औद्योगिक मजबूती और भू-राजनीतिक प्रभाव शामिल हैं। ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था बहुध्रुवीय होती जा रही है और क्षेत्रीय अस्थिरताएं लगातार गहराती जा रही हैं, भारत का रक्षा बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं का दर्पण बन जाता है। आम बजट में रक्षा व्यय में बढ़ोतरी इसी निरंतरता और गंभीरता का संकेत देती है। रक्षा मंत्रालय के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन न केवल पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण को समानांतर रूप से आगे बढ़ाना चाहती है। इस बढ़े हुए बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू उसका संरचनात्मक विभाजन है। कुल आवंटन में से 2.19 लाख करोड़ रुपये सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए रखे गए हैं, जबकि शेष राशि राजस्व व्यय के रूप में वेतन, पेंशन, रखरखाव और प्रशासनिक जरूरतों पर खर्च होगी। पेंशन पर ही 1.71 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान यह बताता है कि रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा पूर्व प्रतिबद्धताओं में बंधा हुआ है। यही वह बिंदु है जहां से 'व्यय की गुणवत्ता' की बहस शुरू होती है। सवाल केवल यह नहीं है कि कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, बल्कि यह है कि वह पैसा कहां, कैसे और किस रणनीतिक उद्देश्य से खर्च हो रहा है। भारत का सुरक्षा परिदृश्य बीते एक दशक में काफी जटिल हुआ है। उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान के साथ पारंपरिक तनाव, उत्तर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की बदलती तस्वीर—ये सभी कारक भारत को अपनी सैन्य तैयारियों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने को मजबूर करते हैं। ऐसे वातावरण में पुराने सैन्य उपकरणों और प्रणालियों के सहारे आगे बढ़ना संभव नहीं है। आधुनिकीकरण अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। लेकिन आधुनिकीकरण का अर्थ केवल महंगे प्लेटफॉर्म खरीदना नहीं होता। इसका अर्थ है तकनीकी श्रेष्ठता, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमताएं, रियल टाइम इंटेलिजेंस और भविष्य की युद्ध प्रकृति के अनुरूप तैयारी। पिछले कुछ वर्षों में यह सकारात्मक संकेत मिला है कि रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच पूंजीगत व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 9.1 प्रतिशत रही है, जो इससे पहले के दशक की तुलना में लगभग दोगुनी है। इसका सीधा अर्थ है कि अब रक्षा खर्च का अधिक हिस्सा नए प्लेटफॉर्म, हथियार प्रणालियों और तकनीकी उन्नयन पर केंद्रित हो रहा है, न कि केवल वेतन और पेंशन जैसी मदों पर। यह बदलाव रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि बिना तकनीकी निवेश के किसी भी देश की सैन्य शक्ति समय के साथ अप्रासंगिक हो जाती है।

फिर भी, यह स्वीकार करना होगा कि पूंजीगत व्यय अभी भी अपेक्षित स्तर से कम है। रक्षा आधुनिकीकरण एक दीर्घकालिक और पूंजी-सघन प्रक्रिया है, जिसमें एक-एक परियोजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं। उन्नत लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, मिसाइल रक्षा प्रणाली, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित निगरानी तंत्र—ये सभी अत्यंत महंगे हैं। इसके साथ ही तकनीक की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यदि आवंटित धन का उपयोग समय पर और प्रभावी ढंग से नहीं हुआ, तो बढ़ा हुआ बजट भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगा। यहीं पर 'व्यय की गुणवत्ता' का प्रश्न केंद्र में आ जाता है। रक्षा क्षेत्र में अक्सर देखा गया है कि परियोजनाएं समय से पीछे चलती हैं, लागत बढ़ जाती है और अंततः क्षमताओं में वह छलांग नहीं लग पाती, जिसकी योजना बनाई गई थी। इसका कारण केवल वित्तीय नहीं, बल्कि संस्थागत और प्रक्रियात्मक भी है। खरीद प्रक्रियाओं की जटिलता, निर्णय में देरी, तकनीकी मूल्यांकन की सीमाएं और घरेलू उद्योग की अपर्याप्त तैयारी—ये सभी कारक व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यदि इन संरचनात्मक समस्याओं को दूर नहीं किया गया, तो बढ़ा हुआ आवंटन भी केवल आंकड़ों तक सीमित रह जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत पहल ने इस संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में एक नया विमर्श खड़ा किया है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि रक्षा खरीद में स्वदेशी स्रोतों को प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्यपालों की भूमिका पर फिर खिंची तलवारें

> मान लें कि अभिभाषण की प्रथा समाप्त हो जाए, तब क्या यह विरोध खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्यपालों द्वारा विधानमंडलों से पास विधेयकों को रोककर रखने के प्रकरण का कोई पक्का समाधान नहीं निकला है। वस्तुतः समस्या संवैधानिक व्यवस्था में नहीं, राजनीतिक संस्कृति में है।

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक विधानसभाओं में राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव की खबरें इस साल भी आई हैं। ऐसा किसी न किसी रूप में पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। वर्तमान टकराव राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए अभिभाषणों के पढ़ने से जुड़ा है। प्रत्यक्षतः ऐसा अनजाने में नहीं हो रहा है। इन मामलों से जुड़े सभी पक्ष संवैधानिक व्यवस्थाओं और उनसे जुड़ी मर्यादा-रेखाओं से भली भांति परिचित हैं। राज्यपाल जानते-समझते हैं और राज्य सरकारें भी। तब ऐसा क्यों होता है?

इन राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपालों के रिश्ते काफी समय से तनावपूर्ण रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कई बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होने वाले राज्यपालों के 'एट होम' कार्यक्रमों का बहिष्कार कर चुके हैं। मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के बीच सीधा संवाद बहुत कम है। इस वक्त तो चुनाव करीब हैं, इसलिए माहौल में वैसे ही गर्मी भरी है।

दक्षिण के जिन तीन राज्यों में विवाद खड़े हुए हैं, उनमें इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही पार्टियों की सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार के विरोध में हैं। ऐसे विवाद होते ही तभी हैं, जब केंद्र और राज्य की सरकारों का आपसी विरोध हो। बंगाल और पंजाब में भी इससे मिलते-जुलते प्रकरण हुए हैं। राज्यपालों या राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित सरकारों द्वारा तैयार किए गए भाषणों या विशेष संबोधनों को हूबहू पढ़ना एक संवैधानिक परंपरा है। यह ब्रिटिश परंपरा है, जिस पर आधारित भारत की संसदीय प्रणाली में भी उन्हीं परंपराओं के पालन की उम्मीद की जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ, जब ब्रिटिश राजा या रानी ने आधिकारिक भाषण को लेकर ना-नुकुर की हो।

देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बीच बहुत से मामलों में मतभेद थे, पर उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, जिससे संसदीय मर्यादा भंग हो। पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन ने 1998 के गणतंत्र दिवस संबोधन में कुछ बदलाव किया था। कुछ दूसरे मौकों पर भी उन्होंने प्रस्तावित मसौदों में संशोधन किए थे, ताकि भाषण का स्वर और संदेश उनके विचारों के अनुरूप हो। ऐसे मौके संसद से बाहर के वक्तव्यों में ज्यादा देखे गए।

उनके दृष्टिकोण और अब हो रहे टकराव में फर्क है। अब इसने राजनीतिक टकराव की शक्ल ले ली है। मसलन कर्नाटक के प्रसंग को देखें, जहां राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने गत 22 जनवरी को विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए सरकार के तैयार भाषण की केवल तीन लाइन ही पढ़ीं और सदन से बाहर चले गए। गहलोत के इस कार्य को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने असंवैधानिक बताते हुए कहा, संविधान के अनुच्छेद 176 और 163 के तहत राज्यपाल को मंत्रिमंडल की ओर से तैयार पूरा भाषण पढ़ना चाहिए।

उधर राज्यपाल गहलोत सरकार के तैयार भाषण के पैरा नंबर 11 पर नाराज थे, जिसमें इनमें लिखा है कि केंद्र सरकार ने यूपीए काल में शुरू की गई मनरेगा योजना को कमजोर किया है। उसका बजट घटाया है, जिससे ग्रामीण रोजगार प्रभावित हुआ है। वस्तुतः यह केंद्र-राज्य संबंधों का महत्त्वपूर्ण पहलू है। सवाल है कि राज्य सरकारों के पास असहमति व्यक्त करने का क्या यही रास्ता बचा है? और क्या राज्यपालों के पास अपने विवेक का इस्तेमाल करने का अधिकार है? सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकारों को संवैधानिक रूप से सीधे राज्यपाल के माध्यम से केंद्र की आलोचना करनी चाहिए? आखिरकार राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त संवैधानिक पद है। उसे राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, न कि राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में। पर क्या केंद्र सरकार को उनके माध्यम से राज्य सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए?

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के साथ लगातार टकराव चलने के कारण मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानमंडल के पहले सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण की प्रथा को समाप्त करने का समर्थन किया है। देश के आठवें राष्ट्रपति (1987-1992) आर वेंकटरमण ने राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधायिका के समक्ष पारंपरिक अभिभाषण की प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश कई बार की थी। वे इस औपनिवेशिक प्रथा को अनावश्यक और असंवैधानिक मानते थे।

फरवरी 1988 में संसद में अपना पहला अभिभाषण देने से पहले उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि 'मेरी सरकार' के स्थान पर 'सरकार' शब्द का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा, यह प्रथा ब्रिटिश विरासत का हिस्सा है और भारत में प्रासंगिक नहीं है। भारत का संविधान स्वयं जनता द्वारा संविधान सभा के माध्यम से बनाया गया था। ऐसे में देश के राष्ट्रपति द्वारा 'मेरी सरकार' कहना 'अनुचित' है। इस व्यवस्था को समाप्त करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अनुच्छेद 86 और 175 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास विधायिका को संबोधित करने का अधिकार तब भी बना रहेगा।

अतीत में कई राजनेताओं ने राज्यपाल का पद ही खत्म करने का सुझाव दिया है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि अभिभाषण की प्रथा समाप्त हो जाए, तब क्या यह विरोध खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्यपालों द्वारा विधानमंडलों से पास विधेयकों को रोककर रखने के प्रकरण का कोई पक्का समाधान नहीं निकला है। वस्तुतः समस्या संवैधानिक व्यवस्था में नहीं, हमारी राजनीतिक-संस्कृति में है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंतिम भाषण के दौरान यह ऐतिहासिक चेतावनी दी, 'संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे साबित हुए, तो संविधान भी बुरा साबित होगा।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की सफलता केवल इसके प्रावधानों पर नहीं, बल्कि इसे अमल में लाने वालों की नैतिकता और ईमानदारी पर निर्भर करती है।

ऐसे मतभेद और टकराव भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वह काफी कुछ वैसा ही कर रही है जैसा कांग्रेस ने दशकों तक किया। हम सैकड़ों साल पुरानी ब्रिटिश परंपराओं पर देश को चलाना चाहते हैं, तो पिछले कुछ दशकों की अपनी परंपराओं पर भी नज़र डालनी चाहिए। सच यह है कि जब दो विपरीत राजनीतिक विचारों की सरकारें केंद्र और राज्य में होती हैं, तब राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच प्रभावी संवाद चैनल होना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के लिए दोनों के बीच समन्वय की जरूरत होती है।

मूल मुद्दा राज्यपाल पद का राजनीतिकरण है। इसका समाधान क्या है? एक काम फिर भी किया जा सकता है वह है सरकारिया और पंछी आयोग की सिफारिशें। सरकारिया (1983-88) और पंछी आयोग (2007-10) ने राज्यपाल की नियुक्ति में निष्पक्षता, मुख्यमंत्री से परामर्श, और सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चयन की सिफारिश की थी।

दोनों आयोगों का मुख्य उद्देश्य राज्यपाल पद को केंद्र के राजनीतिक एजेंट के बजाय एक तटस्थ संवैधानिक पद बनाना और राज्य के बाहर के व्यक्ति को नियुक्त करना है। इसके अनुसार, संविधान में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जा सकता है कि राज्यपालों की नियुक्ति से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया जाएगा।

ऐसा करने से राज्यपालों और निर्वाचित सरकारों के बीच सभी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाएगा। अलबत्ता महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों पर मतभेद को कम करने और वार्षिक संबोधन जैसी पारंपरिक प्रथाओं पर टकराव से बचने के लिए यह अच्छा प्रस्थान-बिंदु हो सकता है।

प्रेरणा

धरती पर ही बसता है स्वर्ग और नरक का संसार

धरती पर स्वर्ग और नरक की कल्पना अक्सर हम किसी दूर, अदृश्य लोक से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि मृत्यु के बाद कोई न्याय होगा, कोई दरवाज़ा खुलेगा, और तभी तय होगा कि हमें जन्नत मिलेगी या दोज़ख़। लेकिन सूफी परंपरा की गहराई में उतरें तो यह विचार बहुत सरल, बहुत मानवीय और बहुत सीधा हो जाता है—स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं, हमारे कर्मों, हमारे स्वभाव और हमारी चेतना में ही बसते हैं।

एक बार कुछ लोगों ने एक सूफी संत से यही प्रश्न किया कि आखिर जन्नत और दोज़ख़ है क्या। संत ने न कोई धार्मिक ग्रंथ खोला, न कोई लंबा उपदेश दिया। उन्होंने कहा, "कल मेरे साथ चलो, जवाब खुद दिखा दूँगा।" अगले दिन वे लोग संत के साथ निकल पड़े। पहला पड़ाव एक शिकारी के यहां था। वह आदमी जंगल से लौट रहा था, उसके हाथों में मरे हुए जानवर थे। उसका जीवन हिंसा, लालच और निर्दयता से भरा था। सूफी संत ने शांत स्वर में कहा, "देखो, यही दोज़ख़ है। जो जीवन भर दूसरों का खून बहाता है, वह चाहे हँसता दिखे, भीतर से जलता रहता है। इसके लिए यह दुनिया भी नरक है और आगे का रास्ता भी अंधकार से भरा होगा।"

यह बात केवल शिकार तक सीमित नहीं है। आधुनिक जीवन में शिकार के रूप बदल गए हैं। कोई किसी का शोषण करता है, कोई झूठ से किसी की रोज़ी छीन लेता है, कोई सत्ता या धन के नशे में दूसरों को कुचलता है। बाहर से वह सफल, शक्तिशाली या सुखी दिख सकता है, लेकिन भीतर लगातार भय, असंतोष और बेचैनी उसे घेरे रहती है। यह मानसिक अग्नि ही दोज़ख़ है। दोज़ख़ का मतलब केवल आग और सज़ा नहीं, बल्कि वह जीवन है जिसमें शांति, करुणा और प्रेम का अभाव हो।

इसके बाद सूफी संत लोगों को जंगल में रहने वाले एक फ़क़ीर के पास ले गए। वह एक छोटी-सी कुटिया में रहता था। उसके पास न धन था, न वैभव, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा सुकून था। वह संतोष से भरा हुआ था, प्रकृति के साथ एकात्म होकर जी रहा था। सूफी संत ने कहा, "इस व्यक्ति ने आने वाले सुख के लिए आज के लालच का त्याग किया है। इसने इच्छाओं की आग को बुझा लिया है। इसके लिए जन्नत निश्चित है।"

यहाँ जन्नत का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मिलने वाला सुख नहीं है। जन्नत वह अवस्था है जहाँ मन शांत हो, जहाँ इच्छाएँ साधन बनें, मालिक नहीं। फ़क़ीर का जीवन बताता है कि सच्चा सुख वस्तुओं की अधिकता से नहीं, बल्कि भीतर की पूर्णता से आता है। जब मन संतोष में टिक जाता है, तब हर सुबह स्वर्ग जैसी लगती है, हर रात सुकून देती है।

लेकिन सूफी संत की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। तीसरी जगह वे एक साधारण व्यक्ति के घर गए। वह न शिकारी था, न फ़क़ीर। वह परिवार के साथ रहता था, मेहनत करता था, ईमानदारी से कमाता था। उसके घर में प्रेम था, आपसी सम्मान था, दान की भावना थी और सादगी थी। वहाँ न कोई अत्यधिक वैभव था, न घोर त्याग, लेकिन जीवन में संतुलन था। सूफी संत ने कहा, "ऐसे लोगों के लिए यहाँ भी जन्नत है और वहाँ भी जन्नत।"

यह कथन बहुत गहरा है। यह बताता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है। न ही इसका अर्थ केवल उपभोग में डूब जाना है। सच्चा मार्ग संतुलन का है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, दूसरों के साथ प्रेम और न्याय से व्यवहार करता है, तब वह धरती पर ही स्वर्ग रच देता है। उसके घर में शांति होती है, रिश्तों में मिठास होती है, और मन में भय नहीं, विश्वास होता है।

सूफी दर्शन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर, जन्नत और दोज़ख़ किसी दूर की अवधारणाएँ नहीं हैं। वे हमारे हर निर्णय में, हर कर्म में, हर भावना में प्रकट होते हैं। जब हम क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से संचालित होते हैं, तब हम अपने लिए नरक तैयार करते हैं। जब हम करुणा, प्रेम और विनम्रता को चुनते हैं, तब स्वर्ग अपने आप उतर आता है। आज की दुनिया में, जहाँ तनाव, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा हर जगह है, यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। लोग अधिक कमाने, अधिक पाने की दौड़ में भीतर से खोखले होते जा रहे हैं। रिश्ते टूट रहे हैं, मन अशांत है। बाहर की सफलता के बावजूद अंदर एक खालीपन है। यह खालीपन ही आधुनिक नरक है। इसके विपरीत, जो लोग सीमित साधनों में भी संतोष, सेवा और प्रेम का जीवन जीते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा लेते हैं। वही लोग धरती पर स्वर्ग का अनुभव करते हैं।

सूफी संत की यह यात्रा हमें आईना दिखाती है। वह पूछती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम शिकारी की तरह केवल अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, या फ़क़ीर की तरह इच्छाओं पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं, या उस साधारण व्यक्ति की तरह संतुलित जीवन जी रहे हैं जो समाज, परिवार और स्वयं के प्रति जिम्मेदार है।

अंततः स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं, बल्कि अवस्थाएँ हैं। वे हमारे भीतर जन्म लेते हैं और हमारे साथ चलते हैं। मृत्यु के बाद क्या होगा, यह एक रहस्य हो सकता है, लेकिन जीवन के दौरान हम क्या अनुभव करेंगे, यह हमारे हाथ में है। अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, कर्म न्यायपूर्ण हैं और हृदय प्रेम से भरा है, तो यह धरती ही स्वर्ग बन सकती है। और अगर हम लालच, हिंसा और घृणा को पालते हैं, तो यही धरती दोज़ख़ बन जाती है। सूफी संत का संदेश सीधा है—स्वर्ग और नरक को खोजने कहीं दूर मत जाओ। अपने जीवन को देखो, अपने कर्मों को परखो। क्योंकि जो बीज हम आज बोते हैं, वही फल हमें यहीं भी मिलते हैं और आगे भी।

भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है इस वर्ष का बजट

दिनांक 1 फरवरी 2026 को, रविवार के दिन, भारत की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने भारतीय संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में की गई घोषणाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर घटित हो रही उथल पुथल से भारत को बचाने की पुरजोर कोशिश की गई दिखती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा अपने द्वितीय कार्यकाल में वर्ष 2025 के दौरान पूरे वर्षभर लगातार कई देशों के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर टैरिफ की घोषणाएं की जाती रहीं एवं इसके विरोध स्वरूप कुछ देशों ने अमरीका से इन देशों को होने वाले निर्यात पर प्रतिकारी टैरिफ लगाने की घोषणाएं की जाती रहीं। चीन ने तो प्रतिशोध में अमेरिका को दुर्लभ खनिज पदार्थों की आपूर्ति ही रोक दी थी। हालांकि इसके पूर्व अमेरिका ने भी चीन को सेमीकंडक्टर एवं चिप्स की आपूर्ति को प्रभावित करने का प्रयास किया था। कुल मिलाकर, कुछ देश तो आपस में विभिन्न वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को रोकने के प्रयत्न करते रहे। इन सभी घोषणाओं से वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में माहौल विपरीत रूप से प्रभावित होता रहा। ट्रम्प प्रशासन ने भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर भी 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, जो अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ में संभवतः आज अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। इस वित्तीय वर्ष के बजट में तीन कर्तव्यों को ध्यान में रखा गया है। (1) विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए भारत की आर्थिक विकास दर को और अधिक तेज किया जाय ताकि भारत को वैश्विक स्तर पर चल रही उथल पुथल से बचाया जा सके; (2) भारतीय युवाओं में कौशल का विकास करना ताकि तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तनों के लिए वे अपने आप को तैयार कर सकें; (3) देश में समावेशी विकास हो सके एवं भारत के संसाधनों का उपयोग समस्त नागरिकों की भलाई में किया जा सके और कोई भी नागरिक, नगर एवं राज्य आर्थिक विकास की धारा से बाहर नहीं रहे।

वैश्विक स्तर पर उक्त वर्णित परिस्थितियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रही। परंतु, भारत की विकास दर की इस गति को आगामी वर्षों में भी बनाए रखने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। भारत आज दुर्लभ खनिज पदार्थों तथा सेमीकंडक्टर एवं चिप्स का भारी मात्रा आयात करता है। चिप्स को तो आज के उत्पादों के निर्माण में तेल की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। इन दोनों पदार्थों पर चीन एवं अमेरिका का लगभग पूर्णतः एकाधिकार है। भारत अपने आप को इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, इस दृष्टि से बजट में भारत में ही दुर्लभ खनिज पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ओड़िसा, केरल, तमिलनाडु एवं आन्ध्रप्रदेश स्थित खदानों में से कच्चे माल को निकालकर इसे संसाधित करते हुए भारत में ही दुर्लभ खनिज पदार्थों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में उक्त चारों राज्यों में एक कोरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार, भारत में ही सेमीकंडक्टर एवं चिप्स के निर्माण हेतु विनिर्माण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में कई उपायों की घोषणा की गई है एवं इस हेतु 40,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, इसके लिए बजट में सेमीकंडकर मिशन 2.0 को लागू करने की भी घोषणा की गई है। इससे कम्पनियों को भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण इकाईयों को स्थापित करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

हाल ही में भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं, इन समझौतों में 27 विकसित देशों के समूह, यूरोपीयन यूनियन से किया गया मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल है। इसे "मदर आफ ऑल डील्स" कहा जा रहा है क्योंकि यह समझौता 28 देशों (27+1) के बीच एक साथ किया गया सबसे बड़ा समझौता है। इन मुक्त व्यापार समझौतों से भारत में वस्त्र एवं परिधान उद्योग, समुद्रीय पदार्थ उद्योग, चमड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग एवं जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग, आदि को सबसे अधिक लाभ होने जा रहा है। इन उद्योगों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम भारी मात्रा में कार्यरत हैं। भारत में उक्त वर्णित पदार्थों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को रियायतें देने का प्रयास किया गया है ताकि उक्त वर्णित उत्पादों की मांग में होने वाली वृद्धि को पूर्ण किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई फंड भी बनाया गया है। टेक्स्टायल उद्योग को भी विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत में निर्मित वस्त्र एवं परिधानों को विश्व के पटल पर रखा जा सके। साथ ही, बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की व्यवस्था, बायोफार्मा शक्ति के रूप में, इस बजट में की गई है। इससे भारतीय दवा उद्योग को विश्व के मानचित्र पर और आगे ले जाने में सहायता मिलेगी।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में विकसित आधारभूत संरचना की अहम भूमिका रहती है। इस बजट के माध्यम से भारत में आधारभूत संरचना को विकसित करने के उद्देश्य से पूंजीगत खर्चों में भारी भरकम वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत खर्चों के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी, इसे वर्ष 2026-27 के बजट में बढ़ाकर 12.20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2014-15 के बजट में पूंजीगत खर्चों के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। पिछले 13 वर्षों में पूंजीगत खर्चों में 6 गुना से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। पूंजीगत खर्चों में वृद्धि से कई क्षेत्रों में सरकारी निवेश भी बढ़ता है एवं इससे अंततः रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होते हैं। बल्कि, अब तो सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी अपने पूंजी निवेश को बढ़ाना होगा।

अभियान

वात्सल्य की विजय: जब माँ के प्रेम ने ईश्वर को भी बाँध लिया

सनातन परंपरा में प्रेम के अनेक रूप माने गए हैं, पर उनमें जो सबसे सहज, सबसे निश्छल और सबसे शक्तिशाली है, वह है मातृत्व का प्रेम। यही वह भाव है जिसमें न कोई शर्त होती है, न कोई अपेक्षा और न ही किसी प्रतिफल की कामना। इसी वात्सल्य भाव का सर्वोच्च, दिव्य और अद्वितीय स्वरूप माता यशोदा और भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में दिखाई देता है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ऐसा आध्यात्मिक सत्य है, जिसमें यह उद्घाटित होता है कि जब प्रेम पूर्ण हो जाता है, तब सर्वशक्तिमान भी स्वयं को निर्बल बना लेता है और अनंत भी सीमित होने को स्वीकार कर लेता है।

भगवान श्रीकृष्ण का जन्म माता देवकी के गर्भ से हुआ, यह ऐतिहासिक और शास्त्रीय सत्य है। देवकी ने नौ माह तक गर्भ में भगवान को धारण किया, मृत्यु के भय के बीच उन्हें जन्म दिया, किंतु जन्म के कुछ ही क्षणों बाद वह बालक उनसे दूर कर दिया गया। उस क्षण देवकी का हृदय जिस वेदना से गुज़रा होगा, उसकी कल्पना भी कठिन है। फिर भी ईश्वर की लीला ऐसी थी कि मातृत्व का रस, लालन-पालन का सौभाग्य और बालकृष्ण के हर क्षण को जीने का अवसर माता यशोदा को मिला। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि तपस्या, प्रेम और पूर्वजन्मों के संस्कारों का फल था।

माता यशोदा का जीवन यह सिद्ध करता है कि ईश्वर को पाने के लिए केवल ज्ञान या वैराग्य पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रेम की वह पराकाष्ठा चाहिए, जिसमें भक्त स्वयं को भूल जाता है। यशोदा जी कभी यह नहीं सोचती थीं कि उनका पुत्र कोई अवतार है या भगवान है। उनके लिए कृष्ण केवल उनका लल्ला थे, जिनकी रक्षा करना, पालन करना और स्नेह देना उनका एकमात्र धर्म था। यदि उन्हें यह ज्ञान हो जाता कि वे स्वयं भगवान को दुलार रही हैं, तो वात्सल्य का यह भाव टूट जाता। इसलिए भगवान ने स्वयं अपनी माया से उन्हें इस ज्ञान से दूर रखा, ताकि उनका प्रेम शुद्ध और निष्काम बना रहे।

ब्रज की धरती पर कृष्ण की बाल लीलाएँ केवल आनंद के दृश्य नहीं हैं, बल्कि गूढ़ आध्यात्मिक संकेत हैं। जब कृष्ण माखन चुराते हैं, तो वह केवल शरारत नहीं, बल्कि यह संकेत है कि भगवान प्रेम के बिना नहीं रहते। माखन शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है, और कृष्ण उसी को चुराते हैं, जहाँ प्रेम होता है। जब यशोदा उन्हें पकड़ती हैं, डाँटती हैं, तो वह ईश्वर को अनुशासित करने का साहस नहीं, बल्कि माँ का अधिकार होता है। यही अधिकार भक्त को ईश्वर पर तभी मिलता है, जब प्रेम अहंकार से रहित हो।

दामोदर लीला इस वात्सल्य प्रेम का शिखर है। जब माता यशोदा कृष्ण को ओखल से बाँधने का प्रयास करती हैं और हर बार रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ जाती है, तब यह केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि भक्ति-दर्शन का सूत्र है। आचार्यों ने बताया है कि ये दो अंगुल भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा हैं। केवल प्रयास से ईश्वर नहीं बंधते और केवल कृपा से भी नहीं। जब दोनों एक हो जाते हैं, तब ईश्वर स्वयं बंधन स्वीकार करते हैं। अंततः जब यशोदा जी थक जाती हैं, उनके ललाट पर पसीना आ जाता है और हृदय करुणा से भर उठता है, तब कृष्ण स्वयं बंध जाते हैं। यह दृश्य बताता है कि ईश्वर को शक्ति से नहीं, केवल प्रेम से बाँधा जा सकता है।

माता यशोदा का चरित्र केवल एक आदर्श माँ का नहीं, बल्कि एक पूर्ण साधिका का भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पूर्व जन्म में वे 'धरा' थीं और नंद बाबा 'वसुश्रेष्ठ द्रोण'। दोनों ने कठोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उन्होंने कोई ऐश्वर्य, कोई स्वर्ग या मोक्ष नहीं माँगा। उन्होंने केवल यही वर माँगा कि पृथ्वी पर जन्म लेने पर भगवान श्रीकृष्ण में उनकी अविचल भक्ति बनी रहे। यह प्रार्थना अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि इसमें ईश्वर से कुछ पाने की लालसा नहीं, बल्कि ईश्वर से प्रेम करने की आकांक्षा है।

एक अन्य पौराणिक कथा में बताया गया है कि माता यशोदा ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। भगवान ने उन्हें वर दिया कि वे देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे, किंतु मातृत्व का सुख यशोदा को ही मिलेगा। यह वरदान यह दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं तय करते हैं कि वे किस भक्त के प्रेम के अधीन होंगे। यशोदा का प्रेम इतना निष्कपट और निष्काम था कि भगवान ने स्वयं को उनके चरणों में सौंप दिया।

भागवत पुराण में यशोदा को केवल नंद बाबा की पत्नी या कृष्ण की माँ के रूप में नहीं, बल्कि वात्सल्य रस की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भक्ति के नौ रसों में वात्सल्य सबसे दुर्लभ माना गया है, क्योंकि इसमें भक्त स्वयं को ईश्वर से छोटा नहीं, बल्कि बड़ा मानता है। वह ईश्वर की रक्षा करता है, उसकी चिंता करता है और उसके लिए भयभीत होता है। यह भाव तभी संभव है, जब प्रेम पूर्ण हो और अहंकार पूर्णतः समाप्त हो चुका हो।

यह भी कहा गया है कि वैकुण्ठ धाम में एक नित्य यशोदा हैं, जो भगवान श्रीकृष्ण की शाश्वत माता हैं। जब ब्रज में भगवान का अवतरण हुआ, तब वही नित्य यशोदा पाटला-पुत्री यशोदा में आविष्ट हो गईं। इस प्रकार लौकिक और अलौकिक यशोदा एक हो गईं। यह दर्शाता है कि ब्रजलीला केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि दिव्य लीला का पृथ्वी पर अवतरण है।

यशोदा नाम स्वयं में गहरा अर्थ समेटे हुए है। 'यश' और 'दा' से मिलकर बना यह नाम दूसरों को यश और श्रेय देने वाली को दर्शाता है। माता यशोदा ने जीवन भर यही किया। उन्होंने कभी अपने लिए श्रेय नहीं माँगा। कृष्ण की किसी भी लीला का श्रेय उन्होंने स्वयं को नहीं दिया। उनका सारा जीवन त्याग, स्नेह और करुणा से भरा हुआ था। यह त्याग ही उनकी साधना थी।

माता यशोदा केवल कृष्ण की ही नहीं, बल्कि बलराम की भी पालनकर्ता थीं। उन्होंने रोहिणी के पुत्र बलराम को भी अपने पुत्र समान पाला। उनका हृदय सीमित नहीं था। वे समस्त ब्रज के बालकों की माँ थीं। यही कारण है कि ब्रजवासी उन्हें केवल नंदरानी नहीं, बल्कि माँ के रूप में पूजते थे।

यशोदा जयंती इसी वात्सल्य भाव के उत्सव का दिन है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मातृत्व की महिमा का स्मरण है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएँ माता यशोदा और बालकृष्ण की पूजा करती हैं। उनका विश्वास है कि यशोदा जी की कृपा से संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और परिवार में प्रेम, शांति और सौहार्द बना रहता है।

शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री इस दिन निश्छल मन से माता यशोदा और बालकृष्ण की पूजा करती है, उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। किंतु इसका गूढ़ अर्थ केवल जैविक संतान नहीं, बल्कि करुणा, धैर्य और सृजनात्मकता की संतान भी है। जब किसी के भीतर वात्सल्य जागृत होता है, तब वह केवल अपने बच्चे से ही नहीं, बल्कि पूरे संसार से माँ जैसा व्यवहार करने लगता है।

आज के समय में, जब संबंधों में स्वार्थ और अपेक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं, माता यशोदा का आदर्श और भी प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ माँगा नहीं। न यश, न सम्मान, न मुक्ति। उन्होंने केवल प्रेम दिया। यही कारण है कि ईश्वर स्वयं उनके अधीन हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम जब पूर्ण होता है, तब वह ईश्वर से भी बड़ा हो जाता है।

अंततः माता यशोदा का चरित्र यह उद्घोष करता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल और सबसे कठिन मार्ग प्रेम का है। सरल इसलिए कि इसमें कोई कठिन साधना नहीं, और कठिन इसलिए कि इसमें स्वयं को पूरी तरह भूलना पड़ता है। जब अनंत स्वयं को माँ की गोद में सौंप देता है, जब सर्वशक्तिमान रस्सी से बंध जाता है, तब यह सिद्ध हो जाता है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। माता यशोदा उसी शक्ति की साकार प्रतिमा हैं—वात्सल्य की वह पराकाष्ठा, जहाँ भगवान भी बालक बनकर शरण लेते हैं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

विश्व कैंसर दिवस: GCRI बना देश का भरोसेमंद कैंसर उपचार केंद्र, 26,810+ मरीजों को मिला नया जीवन, 9,140+ बाहरी राज्यों से पहुंचे

- वर्ष 2025 में 2.59+ लाख OPD विज़िट्स, 17,800+ सर्जरीज़ और 50,130+ कीमोथेरेपीज़ GCRI में संपन्न
- मात्र 6 महीनों में GCRI में 50 रोबोटिक सर्जरीज़, पिछले 3 वर्षों में 40 अत्याधुनिक HIPEC प्रोसीज़र्स हुए
- 2021–2025 के बीच अत्याधुनिक PET-CT स्कैन भी 1,813 से बढ़कर 6,333 हुई
- अक्टूबर 2021 से संचालित 'नो-कॉस्ट कैंसर स्क्रीनिंग OPD' में अब तक 50,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग, 118 कैंसर केसेस की प्रारंभिक अवस्था में पहचान

जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (GCRI), अहमदाबाद ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि वह केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए कैंसर उपचार, अनुसंधान, रोकथाम और प्रारंभिक पहचान का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है। GCRI के सुदृढ़ीकरण और विस्तार की जो आधारशिला वर्षों पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के दौरान रखी गई थी, उसी सतत नीति-दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए आज मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर उपचार का भरोसेमंद केंद्र बनकर उभरा है। विश्व कैंसर दिवस 2026 के अवसर पर जारी आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में GCRI में 26,810 से अधिक नए कैंसर मरीजों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से 9,147 मरीज गुजरात के बाहर से आए। इनमें सबसे अधिक मरीज मध्य प्रदेश (4,572), राजस्थान (2,678), उत्तर प्रदेश (1,094), महाराष्ट्र (279) और बिहार (288) से पहुँचे। ये आँकड़े बताते हैं कि GCRI अब एक सशक्त 'नेशनल रेफरल सेंटर' के रूप में स्थापित हो चुका है, जहाँ देश के लगभग सभी राज्यों से कैंसर मरीज उपचार के लिए पहुँच रहे हैं।

रोबोटिक सर्जरी और HIPEC के माध्यम से GCRI का सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में क्रांतिकारी कदम

अत्याधुनिक तकनीक से कैंसर उपचार उपलब्ध कराने में गुजरात कैंसर रीसर्च इन्स्टीट्यूट (GCRI) ने नया मानदंड स्थापित कर लिया है। यहाँ अब 50 रोबोटिक असिस्टेड कैंसर सर्जरीज़ और HIPEC (हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी) जैसी अत्याधुनिक उपचार सुविधाएँ भी उपलब्ध हो गई हैं। मात्र 6 महीनों में GCRI में रिकॉर्ड 50 रोबोटिक असिस्टेड कैंसर सर्जरीज़ हुई हैं और वहीं पिछले 3 सालों में कैंसर से संबंधित 40 HIPEC प्रोसीज़र्स भी सफलतापूर्वक की गई हैं। उल्लेखनीय है कि HIPEC एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो पेट के भीतर फैले कैंसर में उपयोग होती है, और अब यह चुनिंदा तकनीक मरीजों के लिए GCRI में उपलब्ध है। इसी तरह PET-CT स्कैन (Positron Emission Tomography - Computed Tomography) भी कैंसर की जाँच और इलाज में इस्तेमाल होने वाली सबसे उन्नत और सटीक तकनीकों में से एक है। आसान भाषा में कहें तो, यह दो अलग-अलग तरह की जाँचों (PET और CT) का एक 'हाइब्रिड' या मिश्रण है जो शरीर के अंदर की बहुत बारीक जानकारी देता है। GCRI में PET-CT जाँच की संख्या भी वर्ष 2021 के सापेक्ष 1,813 से बढ़कर 2025 में 6,333 हो गई है।

विश्व कैंसर दिवस पर GCRI करेगा 500 कैंसर सर्वाइवर्स का सम्मान

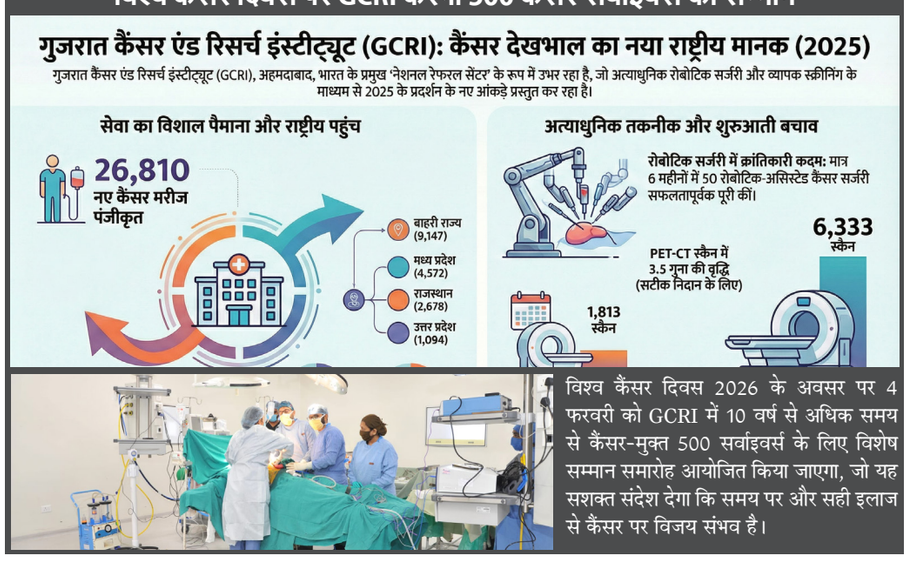

विश्व कैंसर दिवस 2026 के अवसर पर 4 फरवरी को GCRI में 10 वर्ष से अधिक समय से कैंसर-मुक्त 500 सर्वाइवर्स के लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जो यह सशक्त संदेश देगा कि समय पर और सही इलाज से कैंसर पर विजय संभव है।

वर्ष 2025 में GCRI में 2.59+ लाख OPD विज़िट्स, 17,800+ सर्जरीज़ और 50,130+ कीमोथेरेपीज़ संपन्न

कैंसर उपचार में GCRI की बढ़ती विश्वसनीयता से वर्ष 2025 में 2.59+ लाख OPD विज़िट्स दर्ज की गईं। इसी अवधि में 17,800+ सर्जरीज़ जिनमें 50 बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शामिल हैं, हुई हैं। साथ ही, इसी वर्ष कैंसर उपचार के लिए 50,130+ कीमोथेरेपीज़, 5,852 रेडिएशन ट्रीटमेंट्स और 24.6 लाख से अधिक लैब जाँचें भी की गईं। इतना ही नहीं, कैंसर की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए GCRI ने 2025 में पूरे गुजरात में 110 सामुदायिक स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए, जिनमें 12,000 से अधिक लोग शामिल हुए। अक्टूबर 2021 से संचालित 'नो-कॉस्ट कैंसर स्क्रीनिंग OPD' में अब तक 50,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनमें से 118 कैंसर मामलों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हुई। इसी तरह, HIV संक्रमित महिलाओं (PLHA) के लिए चलाए गए HPV DNA स्क्रीनिंग कार्यक्रम में भी 1,400 से अधिक महिलाओं की जाँच की गई जिनमें 21 प्रतिशत HPV पॉजिटिव पाई गईं और आगे की जाँच में 57 सर्विक्स कार्सिनोमा इन-सिटू (CIN) केस सामने आए, जिससे समय रहते इलाज संभव हो सका।

अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली साप्ताहिक स्पेशल परिवर्तित मार्ग से चलेगी

जीएनएस)। दक्षिण रेलवे के चेन्नई एग्मोर (MS) स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य हेतु 60 दिनों का ब्लॉक लिया गया है, जिसके कारण अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

ट्रेन संख्या 09419 अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली साप्ताहिक स्पेशल 05 फरवरी 2026 से 02 अप्रैल 2026 तक परिवर्तित मार्ग वाया रेनिगुंटा-अरक्कोणम नॉर्थ कैबिन-मेलपक्कम-काटपाडी-वेलूर केंट-विल्लुपुरम के रास्ते चलेगी।

इस दौरान यह ट्रेन अरक्कोणम, पेरम्बूर, चेन्नई एग्मोर, ताम्बरम और चेंगलपट्टू स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

ट्रेन संख्या 09420 तिरुचिरापल्ली-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल 08 फरवरी 2026 से 29 मार्च 2026 तक परिवर्तित मार्ग वाया वेलूर केंट-काटपाडी-मेलपक्कम-अरक्कोणम नॉर्थ कैबिन-रेनिगुंटा के रास्ते चलेगी।

इस दौरान यह ट्रेन चेंगलपट्टू-ताम्बरम और चेन्नई एग्मोर, पेरम्बूर, अरक्कोणम स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

मार्ग परिवर्तन के दौरान इस ट्रेन को तिरुत्तणि स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

ट्रेनों के ठहराव, मार्ग और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन

जीएनएस)। नई दिल्ली। डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली एनसीआर द्वारा राजेंद्र भवन में आयोजित वार्षिक मेल-मिलाप कार्यक्रम में डोगरी–पहाड़ी भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और एकता का स्वर ज़ोरदार तरीके से गूंजा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत यह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. कर्ण सिंह ने कहा कि डोगरा समाज को कांगड़ा और चंबा जैसे पड़ोसी पहाड़ी-भाषी क्षेत्रों के साथ मिलकर अपनी सांस्कृतिक एकता को मज़बूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुभाषिक होना समय की ज़रूरत है, लेकिन मातृभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती। यदि नई पीढ़ी को डोगरी बोलने के लिए प्रेरित नहीं किया गया तो यह भाषा आने वाले समय में संकट में पड़ सकती है। डॉ.सिंह ने भाषा संरक्षण में परिवारों, विशेष रूप से माताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए डोगरों से एकजुट, प्रगतिशील और दूरदर्शी बने रहने की अपील की। उन्होंने इस आयोजन के लिए सुदेश डोगरा और समस्त आयोजक टीम को बधाई भी दी। लोकप्रिय डोगरी-हिमाचली लोकगीत "माये निं मेरिये, जम्मूऐ दी राहे, चंबा कितनी क दूर" में कथित छेड़छाड़ के विरोध में प्रसिद्ध गायक धीरज शर्मा ने गीत को उसके मूल शब्दों में प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में ज्योति गुप्ता सहित अन्य कलाकारों ने भी भाग लिया। एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर जम्मू के प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों की चुप्पी पर निराशा व्यक्त की, जबकि लोकगीतों की सांस्कृतिक चिंताओं की हिफाजत में आवाज़ उठाने वाले हिमाचली कलाकारों की सराहना की।

वरिष्ठ पत्रकार और भाषा कार्यकर्ता रमन केसर ने कहा कि लोकगीतों के साथ छेड़छाड़ पश्चिमी पहाड़ी और डोगरी को अलग-अलग दिखाने का प्रयास है, जिसका एसोसिएशन रचनात्मक और सशक्त ढंग से विरोध करेगी। इस अवसर पर रोहित महाजन, क्लस्टर हेड, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को ट्राफियां भेंट कर के सम्मानित किया।

कार्यक्रम के आयोजन में कैलाशपति शर्मा, सुदेश डोगरा, जगदीश शर्मा , कुलवीर सिंह , कर्नल सुनील शर्मा, नेहा शर्मा, सतपाल शर्मा और बोधराज ठाकुर, राज रैना जी का विशेष योगदान रहा।

डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन पिछले चार वर्षों से लोहड़ी के अवसर पर लगातार यह आयोजन कर रही है। एसोसिएशन ने स्वयं को राजनीति से दूर रखा हुआ है और समाजी-सांस्कृतिक कार्यों में लगी हुई है।

' अब तक का सबसे बड़ा समझौता ' - भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर और भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करना निर्यात क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन : फियो अध्यक्ष

जीएनएस)। नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने ' अब तक का सबसे बड़ा समझौता यानी समझौतों के जनक', भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने का तहे दिल से स्वागत किया है, जिसके तहत अमेरिका ने सभी भारतीय निर्मित उत्पादों पर टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति व्यक्त की है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और बढ़ावा देने और मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि है। इस घटनाक्रम को भारतीय निर्यातकों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर और गेम-चेंजर बताते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि यह समझौता अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और सभी क्षेत्रों में भारत के निर्यात विकास को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

श्री रल्हन ने कहा, "भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना और भारत में निर्मित उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है और भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए बड़े अवसर खोलता है।"

श्री रल्हन ने इस बात पर जोर दिया कि इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और परिधान, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, चमड़े के उत्पाद, रत्न और आभूषण, और कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों को टैरिफ युक्तिकरण से काफी फायदा होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, "कम टैरिफ न केवल मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेंगे बल्कि भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक गहराई से एकीकृत होने में भी मदद करेंगे। यह समझौता क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करेगा, नए निवेश आकर्षित करेगा, और निर्यात-उन्मुख उद्योगों में रोजगार सृजन का समर्थन करेगा।"

जैसा कि संकेत दिया गया है, पहले के लगभग 50 प्रतिशत के स्तर से 18 प्रतिशत तक - आपसी टैरिफ में कमी, अन्य एशियाई आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर होगा। उम्मीद है कि इससे उन ऑर्डरों में तत्काल और पर्याप्त वृद्धि होगी जिन्हें पहले रोक दिया गया था, विशेष रूप से परिधान, कपड़ा, चमड़ा और जूते जैसे श्रम- आधारित क्षेत्रों में, जहां वैश्विक खरीदार आमतौर पर दिसंबर तक गर्मियों के मौसम की सोर्सिंग को अंतिम रूप दे देते हैं। बेहतर मूल्य समानता, बेहतर टैरिफ निश्चितता, और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं में मजबूत खरीदार विश्वास के साथ, ये क्षेत्र आने वाले महीनों में ऑर्डरों में तेजी से वृद्धि और निर्यात विकास में तेजी के लिए तैयार हैं।

फियो अध्यक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम और गतिशील नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा निर्यातकों के हितों की रक्षा करने और आपसी फायदे वाले नतीजे पर पहुंचने के लिए अमेरिकी समकक्षों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने में निभाई गई सक्रिय भूमिका की भी सराहना की।

श्री एस सी रल्हन ने कहा, "यह समझौता वैश्विक बाजारों को मुक्त, निष्पक्ष और नियमों पर आधारित व्यापार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संकेत देता है। फियो को विश्वास है कि यह घटनाक्रम भारत को अपने दीर्घकालिक निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और एक विश्वसनीय वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा।"

फियो प्रमुख ने समझौते से मिलने वाले फायदों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी मुद्दे को समय पर हल करने के लिए निर्यातकों और हितधारकों के साथ मिलकर काम करने की फियो की प्रतिबद्धता को दोहराया।

नर्मदा में राजनीतिक भूचाल, भाजपा-कांग्रेस के 1000 से ज्यादा लोग AAP में शामिल हुए

- विधायक चैतर वसावा और दिल्ली के विधायक अखिलेश त्रिपाठी की मौजूदगी में भाजपा-कांग्रेस के हजारों लोग AAP में शामिल हुए
- नर्मदा जिले के चीकदा गांव में AAP की भव्य परिवर्तन सभा आयोजित हुई, विधायक चैतर वसावा ने दी उपस्थिति
- हमारी सरकार में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे – चैतर वसावा
- सरकार बनते ही ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे – चैतर वसावा
- वन अधिकार कानून के तहत लंबित अधिकार अवश्य दिए जाएंगे – चैतर वसावा
- जिले के 181 गांवों में स्कूल नहीं हैं, 505 शिक्षकों के पद खाली हैं – चैतर वसावा
- आदिवासी युवा पुलिस, IAS, IPS, डॉक्टर और शिक्षक बनें, इसके लिए AAP लगातार प्रयासरत – चैतर वसावा
- मनरेगा का नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती, घोटालों का जवाब जनता आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनावों में देगी – चैतर वसावा
- 2027 में गुजरात में परिवर्तन लाकर AAP की सरकार बनाएंगे – चैतर वसावा
- आदिवासियों पर अन्याय होगा तो हम सड़क पर उतरेंगे – चैतर वसावा

जीएनएस)। अहमदाबाद/नर्मदा/भरूच/गुजरात। नर्मदा जिले के चीकदा गांव में AAP की भव्य परिवर्तन सभा आयोजित की गई, जिसमें AAP विधायक चैतर वसावा, दिल्ली से आए विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। विधायक चैतर वसावा और दिल्ली के विधायक अखिलेश त्रिपाठी की मौजूदगी में भाजपा-कांग्रेस के 1000 से भी ज़्यादा लोग AAP में शामिल हुए थे। साथ ही साथ इस सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और AAP को समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज के अधिकारों, विकास और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों पर भाजपा सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और पार्टी आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चैतर वसावा ने कहा कि आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार वर्षों से केवल कागजों पर ही रहे हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही निश्चित रूप से जमीन पर लागू किया जाएगा। सरकार बनते ही आदिवासी समाज की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी और वन अधिकार कानून के तहत जिन लोगों के अधिकार लंबित हैं, उन्हें उनके अधिकार दिए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 505 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में भरा जाएगा। इसके अलावा 181 गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां स्कूल शुरू किए जाएंगे और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। जिले में 1200 से अधिक बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, जिसे दूर करने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी और बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने के प्रयास किए जाएंगे। युवाओं के भविष्य पर बात करते हुए चैतर वसावा ने कहा कि आदिवासी युवा पुलिस, IAS, IPS, डॉक्टर और शिक्षक बनें, इसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार चिंतित और प्रयासरत है। लेकिन भाजपा सरकार की तानाशाही और भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण आदिवासी समाज को उचित अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास की ग्रांट का उपयोग अपने प्रचार और कार्यक्रमों के लिए करती है। आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में सत्ता प्राप्त किए बिना आदिवासी समाज की समस्याओं का समाधान करना कठिन है। उन्होंने 2027 में पूरे गुजरात में परिवर्तन लाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प व्यक्त किया। सांसद मनसुख वसावा पर निशाना साधते हुए आप नेता चैतर वसावा ने सार्वजनिक चर्चा और डिबेट के लिए तैयारी जताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा में कई बार आदिवासी समाज के मुद्दे उठाए हैं, जबकि भाजपा सांसद ने लोकसभा में आदिवासी समाज के लिए क्या किया है, यह जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। विधायक चैतर वसावा ने आगे कहा कि डेडियापाड़ा की जनता की एकता और शक्ति ऐसी है कि आज देश के प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी डेडियापाड़ा आना पड़ता है। आने वाले दिनों में कांग्रेस सहित अन्य दलों के दिग्गज नेता भी डेडियापाड़ा आएंगे, ऐसी जानकारी मिली है। इस मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश-विदेश से कोई भी नेता आए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों में जागरूकता फैलाने, लोगों को एकजुट करने और लोगों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा हो, सड़क हो या मैदान—जहां भी जरूरत पड़े, वे जनता की आवाज उठाते हैं, जो भाजपा सरकार को पसंद नहीं है। भाजपा के कुछ नेता और उनके समर्थक लोगों पर दबाव डालने के लिए फोन करते हैं और लोगों को डेडियापाड़ा न आने देने के प्रयास करते हैं। लेकिन यह शक्ति और हिम्मत केवल मेरी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि मेरे साथ सरपंच, जिला प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकर्ता, युवा, बुजुर्ग तथा माता-पिता का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। इसी जनसमर्थन के कारण मैं इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। मनरेगा सहित विभिन्न मुद्दों पर नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती—ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनावों में देगी। उन्होंने आदिवासी समाज के पारंपरिक वन अधिकारों पर स्पष्ट कहा कि आदिवासी समाज इस जंगल में आदिकाल से निवास करता आया है और लकड़ी, बांस तथा अन्य वन उपज पर उनका अधिकार है। इस मुद्दे पर वन विभाग को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि आदिवासियों पर अन्याय हुआ तो वे सड़क पर उतरेंगे।

पश्चिम रेलवे – अहमदाबाद मण्डल

यार्डस में परिचालनात्मक रूप से आवश्यक रूपांतरणो के संबंध में मौजुदा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव/संशोधन तथा सम्बद्ध कार्य

निविदा सं. DRM-SnT-ADI-Sig 23 of 2025-26 आमंत्रित करती सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए कार्यरत डीआरएम/एस एण्ड टी ई-निविदाएँ आमंत्रित करते हैं। बोलीदाता उनकी मुल/संशोधित बोली केवल बंद होने की तारीख एवं समय तक जमा कर सकते हैं, यह निविदा समक्ष मैन्युअल ऑफर स्वीकार नहिं किया जायेगा और कोई भी मैन्युअल ऑफर प्राप्त होने पर ध्यान नहिं दिया जाएगा।

कार्य का नाम: अहमदाबाद मण्डल के मौजुदा साणंद एवं छारोडी स्टेशन यार्डस में परिचालनात्मक रूप से आवश्यक रूपांतरणो के संबंध में मौजुदा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव/संशोधन करने का तथा सम्बद्ध सिग्नलिंग सामग्री की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और कमीशनींग करने का कार्य।

कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 4,34,34,713.04/- (रूपये चार करोड़ चौंतीस लाख चौंतीस हजार सात सौ तेरह और चार पैसे मात्र)

जमा बयाना राशी: ₹ 3,67,200/- (रूपये तीन लाख सड़सठ हजार दो सो मात्र)

निविदा बंद होने एवं निविदा खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक: 02/03/2026 को 15:00 बजे तक उसके बाद नहिं एवं 02/03/2026 को 15:30 बजे निविदा खोली जायेगी।

ई-निविदा की वेबसाईट: www.ireps.gov.in

ADI-267

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: x.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

विविध कार्य

डब्ल्यू/623/एनआईटी/1, दिनांक : 29/01/2026, मंडल रेल प्रबंधक /मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, के लिये "खुली निविदा" ई–निविदा के माध्यम से वेबसाइट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है।

ई–निविदा सं. एवं कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹)	बयाना राशि (₹)
1. आरटीएम–2025–26–139. चंदेरिया–धोसवास सेक्शन – स्टाफ क्वार्टर (सीओआर, एसएमपी, जीआरएफ एवं एनबीएच रेलवे कॉलोनी) में पानी की आपूर्ति और ड्रेनेज सुविधा का सुधार।	2,34,09,347.19	2,67,100
2. आरटीएम–2025–26–140. नीमच–मंदसौर सेक्शन – एसएसई/पी.वे/नीमच ऑफिस, डिपो और स्टोर में बिजली के काम सहित सुधार।	1,30,49,858.15	2,15,300
3. आरटीएम–2025–26–172. डॉ. अंबेडकर नगर (डीएडीएन) – खराब क्वार्टरों (टी/190ए से एन=14 नग, टी/193ए से एफ–06 नग) के स्थान पर 20 यूनिट टाइप 2 क्वार्टर उपलब्ध कराना जिसमें बिजली का काम भी शामिल है।	4,47,69,420.29	3,73,900
4. आरटीएम–2025–26–173. रतलाम डिवीजन– अजनोद–12 नग और पालिया–08 नग (कुल 20 नग) टाइप 2 क्वार्टर उपलब्ध कराना जिसमें बिजली का काम भी शामिल है।	4,51,08,038.26	3,75,600
5. आरटीएम–2025–26–174. निम्बाहेड़ा– खराब क्वार्टर नं. जी–33ए से एच–8 नग और टी/16ए से बी–2 नग (कुल 10 नग) के स्थान पर टाइप 2 स्टाफ क्वार्टर (10 नग) का निर्माण जिसमें बिजली का काम भी शामिल है।	2,28,76,170.64	2,64,400
6. आरटीएम–2025–26–175. सीएनए–आरटीएम सेक्शन– विभिन्न स्टेशनों, एलसी गेट् और गैंग चौल पर 2 वर्ष के लिए टैंकर से पीने के पानी की आपूर्ति।	54,55,440.64	1,09,100
7. आरटीएम–2025–26–176. बेराच–बेराच केबिन पर एक साथ रिसेप्शन सुविधा के साथ पूरी लंबाई की दूसरी लूप लाइन का प्रावधान।	1,26,11,336.07	2,13,100
8. आरटीएम–2025–26–177. 1. चित्तौड़गढ़– पीएफ लाइन नं 2 (डीएन एमएल), पीएफ लाइन नं. 4 (कॉमन लूप लाइन) और पीएफ नं. 5 (अप लूप लाइन) पर ब्लास्ट लैस ट्रैक का प्रावधान और 2. उज्जैन स्टेशन– पीएफ नं. 1 (डाउन मेन), पीएफ नं. 3/4 (लूप), पीएफ नं. 5 (लूप) और पीएफ नं. 6 (लूप) लाइन पर ब्लास्टलैस ट्रैक का प्रावधान।	33,37,98,534.58	18,19,000
9. आरटीएम–2025–26–179. 1. राजेंद्र नगर–सिंहस्थ 2028 के संबंध में स्टेबलिंग लाइन का प्रावधान और 2. लेकोडा में सिंहस्थ 2028 के संबंध में मौजूदा "डी" क्लास को "बी" क्लास में अपग्रेड करना जिसमें बिजली का काम भी शामिल है।	17,46,63,526.01	10,23,300
10. आरटीएम–2025–26–180. डीईएन नॉर्थ आरटीएम क्षेत्राधिकार के तहत हुक बोल्ट के लिए साइज़ एम–27 लॉक नट एम 027 के लिए सिंगल पीस स्प्रिंग इंसर्टेड रियूजेबल सीज़ नट प्रदान करना और लगाना।	55,71,467.20	1,11,400
11. आरटीएम–2025–26–181. चंदेरिया–रतलाम फतेहाबाद सेक्शन–डिवीजन इंजीनियर (नॉर्थ) रतलाम के क्षेत्राधिकार में टिम्बल गेदो वॉर्सिस ट्रॉली सिस्टम का उपयोग करके प्री और पोस्ट टैम्पिंग ट्रैक माप सर्वेक्षण।	62,07,081.57	1,24,200
12. आरटीएम 2025–26–182. रतलाम डिवीजन–जीआरपी थाना/बैरक में सुधार/मरम्मत (7 स्टेशन – दाहोद एस, एमजीएन, सीओआर, यूजेएन, एसईएच, आईएनडी और डीएडीएन) का सुधार/मरम्मत।	52,45,620.57	1,04,900

अनुमानित मात्रा : क्र.सं.–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए – निविदा अनुसूची के अनुसार। **निविदा प्रपत्र का मूल्य** : क्र.सं.– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए – शून्य। **कार्य समापन अवधि** : क्र.सं.–1, 2, 5, 7, 10, 11 और 12 के लिए – 12 महीने। क्र.सं.– 3, 4 और 9 के लिए– 18 महीने। क्र.सं.– 6 और 8 के लिए – 24 महीने। **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि** : क्र.सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए – 29.01.2026. **निविदा खुलने की तिथि** : क्र.सं. 1 और 6 के लिए – 20.02.2026, क्र.सं. 2, 9 और 12 के लिए – 24.02.2026, क्र.सं. 3, 4 और 5 के लिए– 02.03.2026, क्र.सं. 7 के लिए – 06.03.2026, क्र.सं. 8, 10 और 11 के लिए – 27.02.2026. • विस्तृत निविदा सूचना, अर्हता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइट: www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं।

SNP-440

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

मुख्यमंत्री का ग्रामीण स्तर पर अधिक पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही के साथ विकसित भारत के लिए विकसित ग्राम का कर्तव्य निभाने का सरपंचों से आह्वान

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी की अध्यक्षता में गणेश वासुदेव मावळंकर संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के उपक्रम में गुजरात विधानसभा सचिवालय में 'ग्राम शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम' का शुभारंभ

▸▸ उत्तर गुजरात के 7 जिलों की विभिन्न तहसीलों के 260 से अधिक गांवों के सरपंच सहभागी हुए

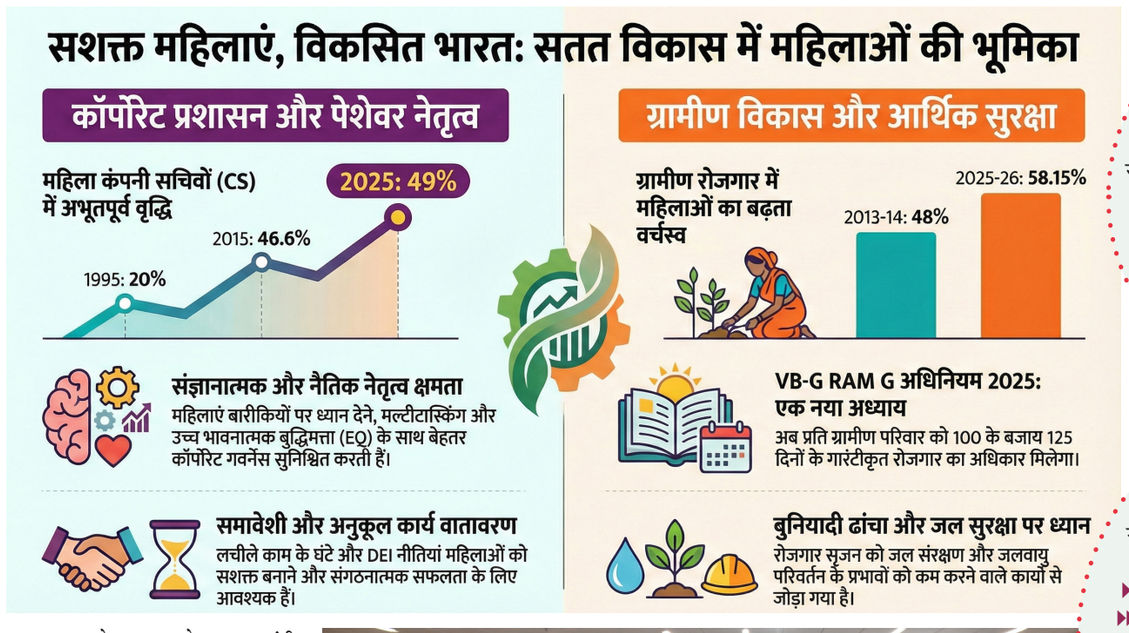

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को ग्राम पंचायतों के सरपंचों को ग्रामीण स्तर पर अधिक पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही के साथ विकसित भारत के लिए विकसित ग्राम का कर्तव्य निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस वर्ष का केंद्रीय बजट भी कर्तव्य को मुख्य आधार बनाकर तैयार किया गया है, इतना ही नहीं इस बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि देश के विकास में गांवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सरपंचों को गांव के मुखिया के रूप में जिम्मेदारीपूर्वक कर्तव्य निभाकर विकसित भारत के निर्माण में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र से जनशक्ति को जोड़ने का प्रेरक मार्गदर्शन दिया।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी तथा मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल एवं श्री कुंवरजीभाई बावळिया की उपस्थिति में गुजरात विधानसभा में गणेश वासुदेव मावळंकर संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के उपक्रम में 'ग्राम शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम' का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर गुजरात के बनासकांठा, वाव-थराद, मेहसाणा, पाटण, साबरकांठा और अरवल्ली जिलों की विभिन्न तहसील के 260 से अधिक सरपंच सहभागी हुए। गांवों को भारत की आत्मा कहा जाता है; इस भावना को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गांव के सभी लोग एक साथ विकास कार्यों में जुड़ते हैं, तब गांव का विकास चमक उठता है।

मुख्यमंत्री ने प्रेरणा देते हुए कहा कि सरपंच के रूप में मिली सेवा के अवसर को अपनी लगन और गांव के विकास के लिए कुछ बेहतर करने की भावना से योजनाबद्ध रूप से विकास कार्यों की सूची बनाकर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सेचुरेशन अप्रोच से 100 प्रतिशत लक्ष्य के साथ अनुदान का उपयोग हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरपंचों की प्राथमिक जिम्मेदारी गांव के सुदूरवर्ती व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है। जब गांवों का विकास होगा, तभी देश का वास्तविक विकास होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के जनहित के कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि गांव के विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर टेक्नोलॉजी के उपयोग से नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाना सरपंचों की जिम्मेदारी है।

किसी भी संकट की घड़ी में सरकार हमेशा उनके साथ है; यह आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने सरपंचों से आह्वान किया कि वे निश्चिंत होकर पूरी निष्ठा से जनसेवा के कार्य करें। उन्होंने सभी को साथ लेकर विकसित गांव से विकसित गुजरात और विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण की मंशा व्यक्त की।

विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी

▸▸ प्रधानमंत्री के 'ग्राम सचिवालय' के मंत्र को साकार कर गांवों को आधुनिक बनाने की जिम्मेदारी सरपंच की है

▸▸ पंचायत अधिनियम में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को जानकर गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सरपंचों को अधिक कार्य करना चाहिए

▸▸ लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए ग्राम सभा में जनभागीदारी अनिवार्य है.

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कर्तव्य के मुख्य आधार को लेकर प्रस्तुत किए गए बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया है

▸▸ देश के विकास की नींव में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका

▸▸ सरपंच गांव के मुखिया के रूप में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ जिम्मेदारीपूर्वक अपना कर्तव्य निभाकर विकसित भारत के निर्माण में ग्रामीण जनशक्ति को जोड़ें

▸▸ जनहित के कार्यों में गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा

▸▸ प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सेचुरेशन अप्रोच से 100 प्रतिशत लक्ष्य के साथ योजनाबद्ध तरीके से अनुदान का उपयोग हो

गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई

गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने 'ग्राम शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम' में उपस्थित राज्य के कर्मठ सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया 'ग्राम सचिवालय' का मंत्र गांवों के विकास को नई दिशा देने वाला है। इस मंत्र को ग्रामीण स्तर पर साकार करने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की मुख्य जिम्मेदारी आप सभी सरपंचों की है।

अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने मुख्यमंत्री के सफल नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की परिकल्पना से ही आज का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम साकार हुआ है। राज्य सरकार गांवों के नागरिकों तक शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। सरपंचों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास केवल ईंट और सीमेंट के निर्माण से नहीं होता, विकास 'संवाद' से होता है। कई बार ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच संवाद की कमी से टकराव होता है। यदि गांव के छोटे से छोटे कार्य में भी ग्राम जनों को विश्वास में लेकर संवाद बढ़ाया जाए, तो संघर्ष स्वतः कम हो जाएगा और जनभागीदारी से गांव का वास्तविक विकास होगा। पंचायती राज के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत अधिनियम में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को समझकर गांव के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना ही सच्ची लोक सेवा है। लोकतंत्र में पंचायत से लेकर संसद तक वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन गांव के हित को सर्वोपरि रखते हुए विपक्ष की अच्छी बातों को भी संवाद के माध्यम से स्वीकार करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि पंचायत लोकतंत्र की नींव है। यदि यह नींव मजबूत होगी, तभी प्रधानमंत्री का 'विकसित भारत' का सपना साकार होगा। उन्होंने सभी सरपंचों से गांवों को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाकर 'विकसित गुजरात' के माध्यम से 'विकसित भारत' के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया गया।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्राम गृह निर्माण मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल ने कहा कि ग्रामीण नागरिकों को शहर की कल्पना से जोड़ने तथा शहर जैसी सुविधाएं गांव में प्रदान कर एक 'आदर्श' गांव बनाने का भगीरथ कार्य आप सभी सरपंचों को करना है। हमारे श्री नरेन्द्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने गांव विकास के हित में 70 प्रतिशत राशि पंचायत की ग्रांट में से उपयोग करने का अधिकार सरपंच को देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। जिससे सरपंच और ग्राम जन मिलकर विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर शहरों के समकक्ष गांवों में सुविधाएं प्रदान कर सकें। गांव के सरपंच ग्रामवासियों के साथ मिलकर यह तय कर सकते हैं कि गांव में कहां सड़क बनानी है, कहां पानी की व्यवस्था बाकी है, कहां लाइट और कहां नाली की सुविधा शेष है। इन सभी सुविधाओं को गांव के हितों को ध्यान में रखकर सरपंच ग्रांट प्रदान कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त श्री ऋषिकेशभाई पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में आज गुजरात के सभी गांवों को कम से कम दो मार्गों से 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना' अंतर्गत जोड़ा गया है। श्री ऋषिकेशभाई पटेल ने कहा कि ग्राम शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी को गांव के प्रशासनिक शिक्षा के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। गांव में सरपंच का पद प्रमुख होता है, इसलिए आप सभी सरपंचों से निवेदन है कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ गांव के वृद्धों, विधवा महिलाओं तथा गांव के उन नागरिकों को, जिन्हें अभी तक सरकारी सहायता नहीं मिली है, उन्हें सेवाओं का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी आप सभी सरपंचों की है।

ग्राम विकास मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावलळिया ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के निर्णयों के परिणामस्वरूप गांवों में शहरों के समकक्ष सुविधाएं मिल रही हैं। गांवों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सीधे ग्राम पंचायत के खाते में राशि दी जाती है। इस राशि का सही दिशा में उपयोग करने से गांव को गोकुल जैसा विकसित गांव बनाया जा सकता है। ग्राम विकास मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.20 लाख रुपए थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने 50 हजार रुपए की वृद्धि की है। यानी कि आगामी दिनों में गांव के नागरिकों को अपना घर बनाने के लिए1.70 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसके अलावा नागरिकों को मनरेगा योजना से शौचालय की सुविधा के लिए 5 हजार रुपए की सहायता दी जाती है। इस प्रकार गांव के प्रत्येक नागरिक को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना घर मिले तथा लोक उपयोगी योजनाओं का लाभ गांव के नागरिकों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सरपंच से अनुरोध किया।

इस अवसर पर विधानसभा सचिव श्री चेतन पंड्या ने स्वागत भाषण देकर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री बालकृष्ण शुक्ल ने आभार विधि की।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सरपंचों को संसदीय लोकतंत्र में पंचायत की भूमिका, जी-रामजी (जी-आरएएमजीआई) ग्राम विकास योजना, पंचायत लेखा नियम तथा ग्राम सभा में सरपंच के अधिकार और कर्तव्यों जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर विकास आयुक्त श्री हितेश कोया, विधानसभा के संयुक्त सचिव श्री रीटा मेहता, उप विकास अधिकारी तथा सरपंच उपस्थित रहे।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में गुजरात की विशेष उपलब्धि

हैदराबाद में आयोजित 'विंग्स इंडिया 2026' में गुजरात को मिला 'बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम' का पुरस्कार

जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात ने अन्य क्षेत्रों की तरह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भी विशेष उपलब्धि हासिल की है। 28 से 31 जनवरी, 2026 के दौरान हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित 'विंग्स इंडिया 2026' सम्मेलन में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री के. राममोहन नायडू ने गुजरात को 'बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ सिविल एविएशन इकोसिस्टम' के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है, यह जानकारी गुजरात के नागर विमानन आयुक्त श्री के. एल. बचाणी ने दी।

गुजरात के नागर विमानन आयुक्त श्री बचाणी ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री के करकमलों से दिया गया यह पुरस्कार गुजरात की उड्डयन क्षेत्र की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं तथा एयरक्राफ्ट लीजिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है। गुजरात के साथ ही तेलंगाना और उत्तराखंड भी इस श्रेणी में संयुक्त रूप से विजेता रहे।

इसके अलावा, नागर विमानन आयुक्त ने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात के विमानन क्षेत्र को आर्थिक विकास का मुख्य इंजन बनाने और अंतिम व्यक्ति तक हवाई कनेक्टिविटी पहुंचाने की राज्य सरकार की दूरदर्शिता को समर्पित है। यह सम्मान विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं विकसित करने और हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए और भी सुलभ बनाने की गुजरात की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले गुजरात को 'विंग्स इंडिया 2022' में 'बेस्ट स्टेट विद ए डेडिकेटेड आउटलुक फॉर द सेक्टर' तथा 'विंग्स इंडिया 2024' में 'बेस्ट स्टेट विद ए डेडिकेटेड लुकआउट फॉर एविएशन सेक्टर' का अवॉर्ड भी मिल चुका है।

पश्चिम रेलवे के 70वें रेल सप्ताह समारोह में भावनगर मंडल के 5 कर्मचारियों को मिला "विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार"

जीएनएस)। मुंबई स्थित यशवंतराव चव्हाण सभागार में सोमवार, 02 फरवरी 2026 को पश्चिम रेलवे के 70वें रेल सप्ताह समारोह के अंतर्गत विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (VRSP)–2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार ने पश्चिम रेलवे के 92 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस प्रतिष्ठित समारोह में भावनगर मंडल के 5 कर्मचारियों को उनके अनुकरणीय कार्य, समर्पण एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है,

जिसका उद्देश्य पश्चिम रेलवे के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता एवं समर्पण को सम्मानित करना है, जो निरंतर चुनौतियों का सामना करते हुए संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। यह पुरस्कार न केवल सम्मान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि अन्य कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनता है। भावनगर मंडल से सम्मानित कर्मचारी:

1.श्री लल्लन प्रसाद वर्मा – ट्रैक मेंटेनर
2.श्री दिनेश कुमार – प्वाइंट्समैन
3.श्री जिंजाला जगदिश मनसुखभाई – मुख्य वाणिज्य निरीक्षक (LSG & NFR)
4.श्री मोहम्मद हनिफ खान – सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट
5.श्री पिन्टु कुमार – टेक्नीशियन

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भावनगर मंडल अपने कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के कारण निरंतर महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है और भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ प्रगति करता रहेगा।

सोना वायदा में 7307 रुपये और चांदी वायदा में 29116 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 6 रुपये फिसला

जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 149830.46 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 55540.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 94285.73 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 38401 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3597.84 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 44352.45 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 145943 रुपये के भाव पर खूलकर, 150000 रुपये के दिन के उच्च और 145943 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 141693 रुपये के पिछले बंद के सामने 7307 रुपये या 5.16 फीसदी की मजबूती के साथ 149000 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 6356 रुपये या 5.37 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 124663 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 863 रुपये या 5.86 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15581 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 143389 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 150710 रुपये और नीचे में 142671 रुपये पर पहुंचकर, 8054 रुपये या 5.71 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 149155 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 146681 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 155300 रुपये और नीचे में 146681 रुपये पर पहुंचकर, 144296 रुपये के पिछले बंद के सामने 9101 रुपये या 6.31 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 153397 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 245711 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 270398 रुपये और नीचे में 245711 रुपये पर पहुंचकर, 236261 रुपये के पिछले बंद के सामने 29116 रुपये या 12.32 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 265377 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 29051 रुपये या 11.94 फीसदी की बढ़त के साथ 272277 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 29386 रुपये या 12.1 फीसदी की तेजी के संग 272229 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। मेटल वर्ग में 8287.12 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 60.2 रुपये या 4.94 फीसदी की तेजी के संग 1279.15 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 1 रुपये या 0.31 फीसदी औंधकर 324 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 1.85 रुपये या 0.59 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 313.55 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 10 पैसे या 0.05 फीसदी की नरमी के साथ 192.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कमोडिटी वायदाओं में 55540.87 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 94285.73 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 44352.45 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38401 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2701.92 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5607 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5637 रुपये और नीचे में 5515 रुपये पर पहुंचकर, 6 रुपये या 0.11 फीसदी घटकर 5619 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 14 रुपये या 0.25 फीसदी लुढ़ककर 5618 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 300 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 300 रुपये और नीचे में 286.5 रुपये पर पहुंचकर, 294.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 80 पैसे या 0.27 फीसदी की नरमी के साथ 294.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 80 पैसे या 0.27 फीसदी की नरमी के साथ 294.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 995 रुपये पर खूलकर, 5.8 रुपये या 0.59 फीसदी बढ़कर 984 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 28126.45 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 16225.99 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 6963.15 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 519.26 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 56.52 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 737.79 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 750.28 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1937.02 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 7.37 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9838 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 84404 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27663 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 378698 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 43721 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8908 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22105 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 63236 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15373 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 15402 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 37267 पॉइंट पर खूलकर, 38602 के उच्च और 37056 के नीचले स्तर को छूकर, 2219 पॉइंट बढ़कर 38401 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5600 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 7.3 रुपये की गिरावट के साथ 215.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 90 पैसे की नरमी के साथ 25.5 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 2832.5 रुपये की बढ़त के साथ 11021.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5760.5 रुपये की बढ़त के साथ 18316.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 20.51 रुपये की बढ़त के साथ 60.66 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.37 रुपये की गिरावट के साथ 4.01 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5600 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 4.3 रुपये की गिरावट के साथ 200 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 80 पैसे के सुधार के साथ 26.7 रुपये हुआ। सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 4442.5 रुपये की गिरावट के साथ 9028.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 16342.5 रुपये की गिरावट के साथ 24499.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 24.68 रुपये की गिरावट के साथ 30.5 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.65 रुपये की बढ़त के साथ 12.65 रुपये हुआ।